[2008] 3 एस. सी. आर. 438

अब्दुल सतार यूसुफ भाई कुरैशी और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

(2002 की सिविल अपील संख्या 593)

26 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.]

गुजरात आवश्यक वस्तु और पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1958-धारा 4 (1) (बी) और (जी); 4 (2) और 5 (1) -बैलों के वध और बैलों के मांस और बिक्री पर प्रतिबंध के तहत अधिसूचना-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अधिसूचना को बरकरार रखते हुए कि बैलों और बैलों के वध के व्यापार को कम करने के उद्देश्य से प्रतिबंध जारी किया गया था-अपील पर, उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात और अन्य। 2005 (8) एससीसी 534; अखिल भारत गोसेवा संघ बनाम स्टेट ऑफ ए. पी. और अन्य,2006 (4) धारा 162-पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील सं. 593/2002

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के डब्ल्यू. पी. एस. सी. ए. सं. 4343/1996 दिनांक 20.01.2001 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए फखरुद्दीन, डब्ल्यू. ए. नोमानी, इम्तियाज अहमद और नगमा इम्तियाज (मिस इक्विटी लेक्स एसोसिएट्स के लिए)।

प्रत्यर्थी के लिए सौरव कृपाल और हेमंतिका वाही।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी बछड़ों, बैलों और अन्य जानवरों के वध और मांस के बिक्री के व्यवसाय में लगे हुए हैं। रिट याचिका में, उन्होंने गुजरात राज्य द्वारा सरकारी राजपत्र में दिनांक 13.12.1989 को प्रकाशित अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी। यह अधिसूचना गुजरात राज्य आवश्यक वस्तु और पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1958 (संक्षेप में '1958 का अधिनियम') की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (बी) और धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (जी) और उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई थी, जैसा कि गुजरात राज्य पर लागू होता है।

2. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बछड़ों और बैलों के वध के व्यापार को काफी कम करने के लिए उचित प्रतिबंध लगाए गए थे।

3. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना राज्य सरकार की शक्तियों से परे थी और अपीलार्थियों बछड़ों और बैलों के वध और अन्य जानवरों के मांस की बिक्री के अपने व्यवसाय को जारी रखने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती थी और उनके जीवन के अधिकार को भी प्रभावित करती थी।

4. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा मामले का निर्णायक रूप से निर्णय लिया गया है।

5. गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात और अन्य। (2005 (8) एस. सी. सी. 534), इसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बनाया गया था: इसके बाद आक्षेपित कानून, बॉम्बे पशु संरक्षण (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1994 बनाया गया। 1954 के बॉम्बे अधिनियम को "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसे संशोधित अधिनियम की धारा 2 द्वारा आगे संशोधित किया गया था, जो इस प्रकार हैः "2. बॉम्बे पशु संरक्षण अधिनियम, 1954 (इसके बाद 'प्रमुख अधिनियम' के रूप में संदर्भित) में, उप-धारा (1-ए) की धारा 5-(1) में, खंड (सी) और (डी) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-(सी) एक बछड़ा; (डी) एक बैल। (2) उप-धारा (3) में-(i) खंड (क) में, उप-खंड (ii) और (iii) को हटा दिया जाएगा; (यह) खंड (ख) में, 'गाय का बछड़ा' शब्दों के बाद, 'बैल या बैल' शब्द जोड़े जाएंगे।

6. पूर्वगामी कारणों से, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते। सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। बॉम्बे पशु संरक्षण (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का गुजरात अधिनियम 4) को संविधान के अंतर्गत माना जाता है। उच्च न्यायालय में दायर सभी रिट याचिकाओं को खारिज करने का निर्देश दिया जाता है। इसी तरह अखिल भारत गोसेवा संघ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2006 (4) धारा 162) में यह निम्नानुसार देखा गया थाः "64. इस मुद्दे को समाप्त करने से पहले, आइए हम 1994 की सिविल अपील संख्या 3968 में अखिल भारत गोसेवा संघ द्वारा की गई प्रस्तुति (एच) पर विचार करें। अखिल भारत गोसेवा संघ की

ओर से प्रस्तुति (एच) में यह आग्रह किया गया था कि मोहम्मद हनीफ कुरेशी बनाम बिहार राज्य (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 731) में लिया गया निर्णय अल कबीर की किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा क्योंकि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से अलग है। उस निर्णय में, पुराने मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध इस आधार पर हटा दिया गया था कि चारा संसाधनों की कमी थी, जो अखिल भारत गोसेवा संघ के अनुसार अब मौजूद नहीं है। गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात (2005 (8) एस. सी. सी. 534) मामले में यह भी कहा गया है कि पशु आहार संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए, चारा संसाधनों की कमी के कारण पुराने मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। हमारे विचार में, इस स्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान मामले में, हम आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1977 से आते हैं जो किसी विशेष प्रकार के गोजातीय पशु के वध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है।

जबकि मिर्जापुर मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने बॉम्बे पशु संरक्षण (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों पर विचार किया, जो गाय और उसकी संतान के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। जहाँ तक आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1977 का संबंध है, भैंसों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, हमारे विचार में, अखिल भारत गोसेवा संघ की इस प्रस्तुति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम किसी विशेष प्रावधान को निरस्त करने के मामले से संबंधित नहीं हैं जो विशेष प्रकार के गोजातीय जानवरों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। मिर्जापुर केस (ऊपर) में, हालांकि, यह नहीं माना गया था कि अपने आप में गोजातीय मवेशियों के वध की अनुमति देना असंवैधानिक है। यह स्थिति होने के कारण, हम अपीलार्थी के विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं कि- कि प्रस्तुतीकरण (एच) अल कबीर द्वारा भैंसों के वध पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से उनकी सहायता के लिए आ सकता है।

7. ऊपर की स्थिति में, हम निर्देशित करते हैं कि यह अपील निराधार और खारिज करने योग्य है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।